से संशोधित पेट्रोल का प्रयोग शुरू किया गया है।

सरकार चरणबद्ध रूप में सीसा रहित पेट्रोल तथा कैटेलैटिक कनवर्टर लगे वाहनों को शुरू करने तथा स्वच्छ डीजल युक्त वाहनों के लिए कम सल्फर युक्त डीजल शुरू करने की एक व्यापक कार्य योजना चला रही है। पेट्रोल और डीजल के लिए ईंधन गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा देश के 12 प्रमुख शहरों में वाहन प्रदूषण के संबंध में व्यापक सर्वेक्षण किए गए है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों और आटोमोबाइल्स के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से पैदा होने वाले शोर पर नियंत्रण के लिए कार्य संहिताएं तैयार कर ली है। इनमें जन संबोधन प्रणाली, वायुयान आप्रेशन, रेलवे आप्रेशन, निर्माण कार्यकलाप और आतिशबाजी शामिल है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे इन कार्य संहिताओं को संबंधित स्थानीय अधिनियमों के अन्तर्गत अमल में लाएं।

आटोमोबाइल, घरेलू उपस्करों, तथा निर्माण उपकरणों के लिए शोर की सीमाएं अधिसूचित की गई हैं।

प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जन-जागरूकता अभियान चलाए गए है।

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

Functioning of RCCFs

2988. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister or ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Regional Chief Conservators of Forests (RCCFs) are not taking any steps to promote afforestation in various states;

(b) whether it is a fact that they arc active only in preventing release of small plots of land for non-forest use;

(c) whether definite target will be set for the RCCFs to encourage forestation of de-forested land; and

(d) how do Government measure the contribution of the RCCFs to the forest wealth of India?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (CAPT. JAI NARAIN PRASAD NISHAD): (a) and (b) No, Sir.

(c) Afforestation over degraded forest land is the responsibility of the State Government. RCCFs have been monitoring the compliance of the stipulation of approvals given under Forest (Conservation) Act, 1980 and Environmental (Protection) Act, 1986 by the Central Government. The Regional Chief Conservators of Forests are empowered to decide cases for diversion of forest land for non forestry uses upto the extent of 5 ha. except mining and regularisation of encroachment and to process cases between 5 ha. to 20 ha. in consultation with the State Advisory Committee.

(d) As a result of promulgation of Forest (Conservation) Act, 1980, rate of diversion of forest land for non forestry purpose has been brought down from around 1,43,000 ha. per year to about 26,000 ha. per year. Regional offices are continuously interacting with the Governments of State/UTs to ensure compliance of stipulated conditions. With the result of continuous monitoring by the regional offices, an area of 2.37 lakh ha. have been brought under compensatory afforestation.

Stoppage of the Mumbai-Nagercoii Express at Ararvtoooly

2989. SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether any steps have been taken for stopping the Mumbai-Nagercoii Express (6340) at AraWionoly;

(b) whether all the passenger and express trains have a stoppage at Aralvionoly, if not, the reasons for non-stoppage of the said trains; and

(c) number of respresentations sent to Southern Railways General Managers, Divisional Railway Managers at Chennai and Thiruvananthapuram; and the reasons for the delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) No, Sir.

(b) and (c) At present, one pair of express and three pairs of passenger trains are scheduled to stop at Aralvoymoli. Stoppage of 6339/6340 Nagercoil-Mumbai Express at Aralvoymoli is not commercially justified. Information regarding the number of representations received in the Offices of General Manager, Southern Railway, Divisional Railway Managers, Madras and Trivandrum is not readily available.

बेतवा नदी में प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार कारखाने

2990. **श्री राघवजी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बेतवा नदी के प्रदूषण के संबंध में जांच करने हेतु गठित की गई विशेषज्ञ समिति द्वारा इस नदी में अधिकतम प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार पाये गये कारखानों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन कारखानों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ऐसे कारखाने अभी भी कार्यरत हैं; यदि हां, तो इन्हें बन्द करने अथवा इन्हें प्रदूषण रहित बनाने हेतु निर्देश जारी न किये जाने के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) मंडीदीप और विदिशा में बेतवा नदी के कैचमेंट क्षेत्र में स्थित फैक्टरियों की सूची विवरण में दी गई है (नीचे देखिए) बेतवा नदी के प्रदूषण निवारण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार इन उद्योगों में से किसी उद्योग द्वारा नदी में सीधे निस्तारण नहीं किया जाता है। सूचना मिली है कि इन उद्योगों से उत्पन्न होने वाले उपचारित एवं अनुपचारित सीवेज का कृषि के लिए उपयोग किया किया जाता है तथा केवल कृषि क्षेत्रों के रन-आफ मानसून के दौरान प्रारम्भिक वर्षा के जल के साथ नदी में पहुंचता है।

(घ) और (ग) इन इकाइयों के विरुद्ध वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निस्तारण की निगरानी के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मैसर्स सोम डिस्टिलरी, बेहतगंज तथा बद्रिस पेपर, मंडीदीप के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

मध्य प्रदेश के मण्डीदीप एवं विदिशा में उद्योगों की सूची

1. मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र
   - (क) मैसर्स बद्रिस पेपर
   - (ख) मैसर्स सी०जे० जेलाटिन
   - (ग) मैसर्स प्रोग्रेसिव एक्सट्रैक्शन
   - (घ) मैसर्स एटेल
   - (ङ) मैसर्स स्टैण्डर्ड सरफैक्टैंट
   - (च) मैसर्स ल्यूपिन लैब
   - (छ) मैसर्स गोदरेज फूड
2. विदिशा औद्योगिक क्षेत्र
   - (क) मैसर्स शिव शक्ति पेपर मिल
   - (ख) मैसर्स एम०पी० पेपर एंड बोर्ड मिल
   - (ग) मैसर्स सोम ब्रेवरीज लिमिटेड
   - (घ) मैसर्स सोम डिस्टिलरीज लिमिटेड

Constitution of a Recuitment Board for Navodaya Vidyalayas

2991. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Recruitment Board has recently been constituted for Navodaya Vidyalayas;

(b) if so, the date and level at which the decision was arrived at; and

(c) the details of its composition and its functions, jurisdiction and legal status?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RE-